पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अशरफ अली अंसारी उर्फ अशरफ अली एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2018 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 474
17 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत अपीलकर्ताओं की सजा मादक पदार्थों के नमूनों के नमूने लेने, उन्हें सील करने और सुरक्षित रखने में कथित प्रक्रियात्मक खामियों के साथ-साथ स्वतंत्र गवाहों की जांच न करने और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का पालन करने में विफलता के मद्देनजर बरकरार रखी जा सकती है।

हेडनोट्स

- **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 20(बी)(ii)(सी) – *चरस* की बरामदगी – दोषसिद्धि – प्रक्रियागत अनियमितताएँ – नमूना लेने और सील करने में संदेह**

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नमूने लेने और प्रमाणित करने के संबंध में धारा 52ए का पालन न करना–उचित सूची, वजन या फिर से सील करने का कोई सबूत नहीं–बिना किसी कारण के नमूने एफएसएल को भेजने में दो महीने से अधिक की देरी–छेड़छाड़ की प्रबल संभावना।

निर्णय: नमूना लेने की प्रक्रिया और लिंक साक्ष्य अविश्वसनीय; दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं । [पैरा 26-30, 33]

- **एनडीपीएस अधिनियम - धारा 52ए - गैर-अनुपालन - प्रभाव - मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन-अनिवार्य आवश्यकताएं**

  नमूना सील करने पर मजिस्ट्रेट का समर्थन औपचारिक था-सील, मात्रा या नमूना विवरण का कोई स्पष्ट प्रमाणन नहीं-मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में नमूने निकालने और सील करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।

  निर्णय: वैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन; अभियोजन पक्ष का मामला भौतिक रूप से कमजोर हो गया। [पैरा 27-29]

- **आपराधिक कानून - स्वतंत्र गवाह - तलाशी और जब्ती - जांच न किए जाने का प्रभाव**

  जब्ती के समय मौजूद स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई; कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया - पूरा मामला पुलिस अधिकारियों की गवाही पर टिका हुआ था - स्वतंत्र गवाहों का पेश न किया जाना तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब अन्य प्रक्रियात्मक संदेह मौजूद हों।

  निर्णय: अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध है; संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। [पैरा 14, 31]

- **एनडीपीएस अधिनियम - धारा 55 - नमूनों की सुरक्षित अभिरक्षा - नमूने भेजने में देरी - लिंक साक्ष्य**

  नमूने विशेष संदेशवाहक को सौंपे जाने के दो महीने से अधिक समय बाद एफएसएल पहुँचे - विशेष संदेशवाहक की जांच नहीं की गई - देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं - हिरासत की श्रृंखला में टूट की पुष्टि हुई।

निर्णय: पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई; संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। [पैरा 30-33]

- **आपराधिक न्यायशास्त्र - एनडीपीएस मामलों में सबूत के मानक - प्रक्रिया की कठोरता - संदेह का लाभ**

एनडीपीएस अपराधों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है - यहां तक कि छोटी-मोटी चूक भी मुकदमे की निष्पक्षता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है - भरोसेमंद लिंक साक्ष्य और उचित नमूने के अभाव में, दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

निर्णय: प्रक्रियात्मक उल्लंघन और अधूरे लिंक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कानून में टिक नहीं सकती। [पैरा 19-20, 28, 33]

न्याय दृष्टान्त

मोहम्मद खालिद बनाम तेलंगाना राज्य, ए आई आर ऑनलाइन 2024 एससी 134–पर भरोसा किया गया; सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 2023 एससी (सप) 1010-पर भरोसा किया गया; भारत संघ बनाम मोहनलाल, (2016) 3 एससीसी 379–इसके बाद; मौसम सिंघा रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2003) 12 एससीसी 377–लागू

अधिनियमों की सूची

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985–धारा 20(बी)(ii)(सी), 52 ए, 55, 57; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 313, 311

मुख्य शब्दों की सूची

एनडीपीएस दोषसिद्धि; चरस जब्ती; नमूना लेने में अनियमितता; सुरक्षित अभिरक्षा; एफएसएल प्रेषण में देरी, स्वतंत्र गवाह; धारा 52 ए अनुपालन,

प्रक्रियागत चूक; साक्ष्य जोड़ना; छेड़छाड़ की संभावना; न्यायिक प्रमाणीकरण; संदेह का लाभ

प्रकरण से उत्पन्न

बेतिया , पश्चिम चंपारण द्वारा परीक्षण संख्या 32/2013 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए दिनांक 20.02.2018 को दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता; श्री रौशन राज, अधिवक्ता; सीतेश कश्यप, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 474

थाना-कांड संख्या-716 वर्ष-2012 थाना- बेतिया शहर जिला-पश्चिमी चंपारण से उत्पन्न

==========

1. अशरफ अली अंसारी उर्फ अशरफ अली, पिता- सफीक अंसारी, निवासी ग्राम/मोहल्ला-चौधराना, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर।
2. बबलू हजाम, पिता- निज़ामुद्दीन हजाम, निवासी ग्राम/मोहल्ला- खेतारी, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थियों के लिए : श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता
श्री रौशन राज, अधिवक्ता
श्री सितेश कश्यप, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, अ.लो.अ.

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

दिनांक: 17-06-2025

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संजीव कुमार और राज्य की विद्वान अ.लो.अ. सुश्री शशि बाला वर्मा को सुना गया।

2. वर्तमान आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं अर्थात् अशरफ अली अंसारी *उर्फ* अशरफ अली और बबलू हजाम द्वारा विद्वान 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेतिया, पश्चिम चंपारण की अदालत द्वारा दिनांक 20.02.2018 को पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जो बेतिया टाउन थाना कांड संख्या 716/2012 से उत्पन्न ट्रायल संख्या 32/2013 के संबंध में है, जो स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस एक्ट') की धारा 20, 22, 23, 24, 27ए और 29 के तहत दर्ज किया गया था, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) के जुर्माने के साथ 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष की कहानी:-

3. प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:-

05.10.2012 की रात में 2:30 बजे, सुचक, अर्थात् नगर पुलिस स्टेशन, बेतिया के उप-निरीक्षक-सह-स्टेशन हाउस अधिकारी, नरेश कुमार को एक गुप्त सूचना मिली कि एक कुख्यात और फरार आरोपी समीर अंसारी ने अपने शूटर अली को गुलाबबाग के निवासी पुन्नू श्रीवास्तव को गोली मारने के लिए भेजा था और उक्त शूटर उस दिन सुबह पुन्नू श्रीवास्तव पर हत्या का प्रयास करने का इरादा रखता था और करने जा रहा था। इसके बाद, उन्होंने (सुचक) पुलिस रजिस्टर में एक सनहा दर्ज किया और पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में 'एस.पी.'), बेतिया को भी उक्त गुप्त जानकारी के बारे में सूचित किया और फिर, एस.पी., बेतिया द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, अनुमंडल पुलिस अधिकारी (संक्षेप में 'एस.डी.पी.ओ.'), सदर बेतिया के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया, जिसमें मुफ्फसिल थाना, नतून थाना, बैरिया थाना, श्रीनगर पुजहा थाना, पनपतिया थाना, मनुआपुल थाना के थानाध्यक्षों के साथ-साथ उक्त थानों में पदस्थापित कुछ अन्य पुलिस पदाधिकारी क्रमशः यूसुफ अंसारी, प्रमोद कुमार राय, अनिल राम, प्रमोद प्रसाद, मुकेश कुमार, नरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश चौहान और विजय कुमार सिन्हा को उक्त पुलिस टीम का सदस्य बनाया गया और उन्हें चार उप टीमों में बांटा गया। सुचक के अनुसार, वह, पुलिस उप-निरीक्षक यूसुफ अंसारी, उप-निरीक्षक विजय कुमार

सिन्हा, उप-निरीक्षक अनिल राम, सभी नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे और श्रीनगर पुझा थाना के थानाध्यक्ष को पावर हाउस चौक पर निगरानी रखने का निर्देश मिला, जबकि अन्य पुलिस अधिकारियों को अन्य स्थानों पर तैनात किया गया था। लगभग 5:30 बजे सुबह, एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल को पूर्वी तरफ से आते देखा गया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने रुकने का संकेत दिया, लेकिन सवार पुलिस दल को देखकर भागने लगे, फिर भी उन्हें पुलिस अधिकारियों ने अन्य पुलिस अधिकारियों की मदद से पकड़ लिया। इसके बाद, दो व्यक्ति, पंकज मोहन सिंह, निवासी लाल बाजार और मोहम्मद आलम, निवासी नानजी चौक, दोनों नगर थाना बेतिया के अंतर्गत, जो संबंधित समय के दौरान उस स्थान के पास से गुजर रहे थे, को पुलिस दल ने गवाह बनाया, जिनकी उपस्थिति में रोकी गई मोटरसाइकिल, जिसका पंजीकरण संख्या बीआर 22 एम/2639 है, की जाँच की गई और जब मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों से उनके नाम पूछे गए, तो उन्होंने अपना नाम अशरफ अली अंसारी उर्फ अशरफ अली (अपीलकर्ता संख्या 1) और बबलू हजाम (अपीलकर्ता संख्या 2) बताया। पंकज मोहन सिंह और मोहम्मद आलम की उपस्थिति में पुलिस दल ने दोनों अपीलार्थियों की तलाशी ली। अशरफ अली अंसारी की कमर के पिछले हिस्से से अमेरिका में बनी एक अर्ध स्वचालित पिस्तौल बरामद की गई और उसमें एक मैगजीन भरी हुई पाई गई, जिसमें पांच जिंदा गोलियां मिली थीं। आरोपी अशरफ अली की जींस पैंट के दाहिने सामने की जेब से, सफेद प्लास्टिक सामग्री में लिपटे भूरे रंग के पदार्थ वाले दो पुडिया (छोटे पैकेट) बरामद किए गए, जिनका वजन लगभग 20 ग्राम था और पूछताछ करने पर, उक्त आरोपी ने जब्त की गई सामग्री का खुलासा नेपाली *चरस* के रूप में किया, हालांकि वह जब्त की गई मोटरसाइकिल,

आग्नेयास्त्रों और मादक पदार्थों के अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका और इन वस्तुओं को अपने कब्जे में रखने के लिए संतोषजनक जवाब भी नहीं दे सका। आरोपी बबलू हज़म की कमर के बाएँ हिस्से से, पुलिस दल ने एक देशी अर्ध-स्वचालित पिस्तौल बरामद की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी, और एक मैगज़ीन से भरी हुई थी, जिसमें पाँच जीवित गोलियां मिली थीं। इसके बाद मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई और मोटरसाइकिल की डिक्की में दो पीले रंग के प्लास्टिक के पैकेट पाए गए और उक्त पैकेटों से कुल 63 भूरे रंग की छोटी गेंदें मिलीं और पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों/अपीलकर्ताओं ने बताया कि ये सामग्री नेपाली *चरस* है, जिसका वजन करने पर वजन 2 किलोग्राम पाया गया और अपीलकर्ताओं ने यह भी बताया कि समीर अंसारी नामक एक व्यक्ति ने उन्हें जब्त की गई मादक सामग्री इस निर्देश के साथ दी थी कि इसे बीरगंज (नेपाल में) से बनारस ले जाया जाए। इसके बाद, अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ स्वतंत्र गवाह पंकज मोहन सिंह और मोहम्मद की उपस्थिति में सुचक आलम ने आरोपी व्यक्तियों की मोटरसाइकिल, पिस्तौल के साथ गोलियां, मोबाइल फोन और मादक पदार्थ जब्त किए, जिसके बारे में स्वतंत्र गवाहों सहित सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ मौके पर एक जब्ती ज्ञापन भी तैयार किया गया था, जिसकी एक प्रति गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई थी, जिन्होंने उसकी प्राप्ति के संबंध में जब्ती ज्ञापन की दूसरी प्रति पर भी अपने हस्ताक्षर किए थे। सुचक के अनुसार मोटरसाइकिल और अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी के संबंध में एक अलग रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। सुचक के अनुसार, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद,

जब्ती ज्ञापन की तैयारी के समय एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4. कथित वस्तुओं की तलाशी और जब्ती से संबंधित घटना के उपर्युक्त विवरण के आधार पर, सूचक नरेश कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष, टाउन पुलिस स्टेशन बेतिया ने अपना आत्म बयान (प्रदर्श-2) दर्ज किया और उसी के आधार पर, टाउन (बेतिया) थाना कांड संख्या 716/2012 के तहत एक औपचारिक प्राथमिकी अपीलकर्ताओं और एक व्यक्ति समीर अंसारी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 22, 23, 24, 27ए और 29 के तहत दर्ज की गई, जिसने आपराधिक कानून को गति प्रदान की।

5. जाँच पूरा होने के बाद, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 93/2013 दिनांक 31.03.2013 के माध्यम से कथित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था और तीसरे आरोपी समीर अंसारी के खिलाफ जाँच लंबित रखी गई थी और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी।

6. दोनों अपीलार्थियों पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (बी)(ii)(सी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसे पढ़ा गया और उन्हें हिंदी में समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और आरोपित अपराध के लिए मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष के सात गवाहों से पूछताछ की जो इस प्रकार हैंः

	नाम	प्रासंगिकता
अ.सा-1	धनंजय चौधरी	तलाशी एवं जब्ती दल का सदस्य

अ.सा-2	विजय कुमार सिन्हा	तलाशी एवं जब्ती दल का सदस्य
अ.सा-3	यूसुफ अंसारी	तलाशी एवं जब्ती दल का सदस्य
अ.सा-4	अनिल राम	तलाशी एवं जब्ती दल का सदस्य
अ.सा-5	नरेश कुमार	सूचना देने वाला
अ.सा-6	प्रमोद कुमार राय	जाँच अधिकारी
अ.सा-7	जितेंद्र प्रसाद सिंह	मालखाना प्रभारी

8. दस्तावेजी साक्ष्य में, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया और उन्हें प्रदर्शित कराया, जो इस प्रकार हैंः

प्रदर्श-1	जब्ती ज्ञापन
प्रदर्श-1/ए	जब्ती ज्ञापन पर सुचक के हस्ताक्षर
प्रदर्श-2	फर्दबयान
प्रदर्श-2/ए	फर्दबयान पर सुचक के हस्ताक्षर
प्रदर्श-2/बी	फर्दबयान पर अग्रेषण नोट के नीचे थानाध्यक्ष टाउन बेतिया थाना के हस्ताक्षर
प्रदर्श-2/सी	सुचक के स्व-कथन पर समर्थन
प्रदर्श-3, 3/ए	औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर
प्रदर्श-4	चार्जशीट
प्रदर्श-5	एफएसएल रिपोर्ट

9. अभियोजन पक्ष ने जब्त की गई मादक सामग्री भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश की, जिसे सामग्री प्रदर्शनी 'I' और 'II' के रूप में चिह्नित किया गया था।

10. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लेने के बाद, दोनों अपीलकर्ताओं के बयान द.प्र.स. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिससे उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर मिला, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से नकार दिया और उन्होंने खुद को निर्दोष होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में खुद को निर्दोष होने का दावा करने के अलावा कोई विशेष बचाव नहीं किया।

11. यहाँ, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय द्वारा द.प्र.स. की धारा 313 के तहत अपीलार्थियों के बयान दो बार दर्ज किए गए थे क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद साक्ष्य में एफएसएल रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके लिए अभियोजन पक्ष की प्रार्थना को विचारण न्यायालय द्वारा द.प्र.स. की धारा 311 के तहत अनुमति दी गई थी और इस कारण से, एफएसएल रिपोर्ट से संबंधित नए साक्ष्य के आलोक में अपीलार्थियों के बयान फिर से दर्ज किए गए थे।

12. दोनों अपीलार्थियों ने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

13. अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के कब्जे से कथित मादक पदार्थों की बरामदगी को साबित करने में सफल रहा है, जो कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), पटना द्वारा रासायनिक जांच में *चरस* पाया गया था और अभियोजन पक्ष भी अपीलार्थियों के शारीरिक रूप से सचेत कब्जे से उक्त प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी को साबित करने में सफल रहा है और कथित प्रतिबंधित पदार्थ की खोज और जब्ती के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुसंगत रहे हैं। विद्वत विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि *चरस* की जब्ती, जब्ती सूची तैयार करना और प्राथमिकी दर्ज

करना अ.सा.-5 (सूचना देने वाला) के साक्ष्य से साबित हुआ और जब्त की गई वस्तुओं को अ.सा-7 द्वारा सीलबंद हालत में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर जब्ती अधिकारी अ.सा-5 के हस्ताक्षर थे और विद्वान विचारण न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित प्रतिबंधित वस्तु की तलाशी और जब्ती के साथ-साथ उसका नमूना लेने के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने की ओर इशारा नहीं किया।

<u>अपीलार्थियों के वकील की ओर से प्रस्तुतियाँ-</u>

14. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री संजीव कुमार ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, दो स्वतंत्र गवाहों, पंकज मोहन सिंह और मोहम्मद आलम के समक्ष मादक पदार्थों की खोज और जब्ती की पूरी प्रक्रिया की गई थी। लेकिन उनमें से किसी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और उनसे पूछताछ नहीं की गई, जिसके बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और यह स्वीकार किया जाता है कि वसूली का कथित स्थान एक व्यस्त सार्वजनिक स्थान पर स्थित था, लेकिन इसके बावजूद अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के भौतिक और सचेत कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थों की कथित वसूली को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से पूछताछ करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों से उचित तरीके से नमूने लेने के तथ्य को साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी विफल रहा और इसके अलावा, पुलिस दल द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उपधारा 2 के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया

और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सफेद प्लास्टिक में लिपटे दो छोटे पैकेट और पीले रंग के प्लास्टिक में लिपटे दो अन्य पैकेट अपीलकर्ताओं के भौतिक कब्जे के साथ-साथ उनकी मोटरसाइकिल से भी पाए गए। इसलिए, इन चार बरामद वस्तुओं को देखते हुए, प्रत्येक जब्त वस्तु से चार प्रतिनिधि नमूने लिए जाने चाहिए थे, लेकिन इस संबंध में, आई.ओ. द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि नमूने लेने से पहले, इन चारों जब्त वस्तुओं की सामग्री मिश्रित थी या प्रत्येक पैकेट से अलग-अलग नमूने लिए गए थे, इसलिए, नमूना लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण थी और यहां तक कि अभियोजन पक्ष भी विश्वसनीय साक्ष्य के साथ उक्त नमूने को साबित करने में विफल रहा, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने नमूने लेने के स्थान के बारे में विरोधाभासी बयान दिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सुचक नरेश कुमार (अ.सा-5) के साक्ष्य के अनुसार, जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को नगर (बेतिया) थाना के थानाध्यक्ष नरेश कुमार की मुहर के साथ बरामदगी के स्थान पर सील कर दिया गया था, इसलिए, यदि जब्त प्रतिबंधित माल से नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे, तो जब्त माल को संबंधित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक अन्य सील के साथ नमूने लेने के बाद फिर से सील किया जाना चाहिए था, लेकिन संबंधित थाने के *मालखाना* प्रभारी अ.सा-7 के अनुसार, जिन्होंने जब्त प्रतिबंधित माल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीलबंद अवस्था में पेश किया था, सीलबंद माल में सुचक नरेश कुमार की सील लगी हुई थी, जो कि संभव नहीं था यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्त प्रतिबंधित माल की पहली सील तोड़ने के बाद नमूने लिए गए होते, जो कि सुचक या जांच अधिकारी की ओर से जब्त प्रतिबंधित माल की सील करने की प्रक्रिया में कुछ हेरफेर को

दर्शाता है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि दो पार्सलों में रखे गए नमूने जांच अधिकारी के अनुरोध पर संबंधित अदालत द्वारा उन नमूनों को एफ.एस.एल., पटना भेजने के लिए ज्ञापन संख्या 3312 दिनांक 06.11.2012 के माध्यम से पुलिस को सौंप दिए गए थे, लेकिन उक्त पार्सल एफ.एस.एल., पटना के कार्यालय में 19.01.2013 पर यानी दो महीने से अधिक समय बाद पहुंचे, जिससे विशेष दूत, अर्थात् सत्येंद्र तिवारी या किसी और द्वारा नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने की प्रबल संभावना पैदा होती है और उक्त देरी को केवल विशेष दूत द्वारा समझाया जा सकता था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश और जाँच नहीं किया गया था। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों का भी जांच अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया था।

15. उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने **एआईआर ऑनलाइन 2024 एससी 134** में दर्ज **मोहम्मद खालिद बनाम तेलंगाना राज्य** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि जब्ती के समय से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक नमूनों को सुरक्षित रखने को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था और एफएसएल रिपोर्ट में नमूनों पर अभियुक्त के पंच चिट, मुहर और हस्ताक्षर के बारे में खुलासा नहीं किया गया था और जांच अधिकारी द्वारा सूची तैयार करने और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों का पालन न करने को भी ध्यान में रखा गया था। उक्त फैसले के पैराग्राफ

संख्या 20, 21 और 22 में की गई टिप्पणियों को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"20. दो स्वतंत्र पंच गवाहों यानी शरीफ शाह और मिथुन जाना, जो वसूली की कार्यवाही में शामिल थे, से साक्ष्य में पूछताछ नहीं की गई और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही थी।

21. अ.सा.-5 की गवाही के अनुसार, गांजे के तीन नमूने तैयार करने वाले उप-निरीक्षक एलडब्ल्यू-10 की साक्ष्य में जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने न तो किसी गवाह से पूछताछ की और न ही जब्ती के समय से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक नमूनों को सुरक्षित रखने के संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया। जिस अधिकारी ने पुलिस स्टेशन से नमूने एकत्र किए और उन्हें एफ.एस.एल. में ले गए, परीक्षण में उनकी जांच नहीं की गई। जब्ती अधिकारी (निरीक्षक अ.सा.-1) के साक्ष्य के उद्धृत हिस्से से यह स्पष्ट है कि उसने तीन नमूनों में से एक को आरोपी को सौंप दिया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पंचनामे में नमूनों को सील करने का उल्लेख नहीं किया था। अ.सा.-1 के साक्ष्य के विपरीत, अ.सा.-5 ने कहा कि गांजे के तीन नमूने उप-निरीक्षक एलडब्ल्यू-10 द्वारा निकाले गए थे और गवाह को सौंप दिए गए थे, जिन्होंने इसे एसीपी को एफएसएल भेजने के लिए भेज दिया था। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया कि संपत्ति मालखाने में रखी गई थी। मालखाना रजिस्टर अदालत में पेश नहीं किया गया था। एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) पंच चिट और

मुहरों और नमूनों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर के बारे में खुलासा नहीं करती है। अदालत (मुद्दामल) में जमा की गई संपत्ति पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने मुद्दमल गांजे के मूल तीन पैकेटों को सुरक्षित रखने के लिए सात नए थैलों में बदलने के लिए अदालत से कोई अनुमति नहीं ली थी। अभियोजन पक्ष के मामले में ये स्पष्ट खामियां एक अपरिहार्य निष्कर्ष को जन्म देती हैं कि अभियोजन पक्ष जब्ती के समय से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक नमूने के पैकेटों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक लिंक साक्ष्य को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। बल्कि, तीन नमूनों को एफएसएल को भेजे जाने की संभावना इस तथ्य से नकार दी जाती है कि जब्ती अधिकारी ने एकत्र किए गए तीन नमूनों में से एक को आरोपी को सौंप दिया। इस प्रकार, उनके केवल दो नमूने रह गए जबकि तीन नमूने एफएसएल में पहुंचे। यह विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है।

22. मान लीजिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत जांच अधिकारी अ.सा.-5 द्वारा एक सूची तैयार करने और क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-11) और कुछ नहीं बल्कि एक बेकार कागज है और इसे सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। आरोपी ए-3 और ए-4 को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत अपराध भांग के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात या निर्यात से

संबंधित है। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि आरोपी ए-3 और ए-4 के पास गांजा पाया गया था। अभियोजन पक्ष का सर्वोच्च मामला जो किसी भी स्वीकार्य या ठोस साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, वह यह है कि इन दोनों अभियुक्तों ने ए-1 और ए-2 के साथ गांजे की बिक्री/खरीद की साजिश रची थी। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ए-1 और ए-2 के पूछताछ नोटों पर आधारित है।"

16. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसकी रिपोर्ट **एआईआर 2023 एससी (एसयूपीपी) 1010** में की गई है, जिसमें नमूने लेने की प्रक्रिया के संबंध में **भारत संघ बनाम मोहनलाल और अन्य (2016)3 एससीसी 379** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया गया है और अभियुक्त/अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहनलाल** (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कथित प्रतिबंधित सामग्री से नमूना नहीं लिए जाने के कारण अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह जताया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 8, 9 और 10 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"8. मोहनलाल के मामले में इस अदालत के फैसले के पैराग्राफ 15 से 17 में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

"15. धारा 52-ए (2) में यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के बाद उसे या तो निकटतम पुलिस थाने के

प्रभारी अधिकारी को या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जो उक्त प्रावधान में निर्धारित सूची तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा, जिसका उद्देश्य (क) सूची की सत्यता को प्रमाणित करना, (ख) मजिस्ट्रेट के समक्ष ली गई ऐसी औषधियों या पदार्थों की तस्वीरों को सत्य प्रमाणित करना और (ग) मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेना और इस प्रकार लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणित करना है।

16. धारा 52-ए की उपधारा (3) के अनुसार मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र आवेदन स्वीकार करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही जब्ती की जाती है और प्रतिबंधित माल पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या सशक्त अधिकारी को भेजा जाता है, संबंधित अधिकारी कानूनन बाध्य है कि वह उपरोक्त उद्देश्यों के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करे, जिसमें उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना शामिल है, जिसके बाद नमूनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इस प्रकार निकाले गए नमूनों की सूची की सत्यता को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को उसके द्वारा सत्य प्रमाणित किया जाना चाहिए।

17. जब्ती के समय नमूने लेने का प्रश्न, जो प्रायः मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजना में नहीं उठता। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की धारा 52-ए(4) के अनुसार, धारा 52-ए की उपधारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए और प्रमाणित नमूने मुकदमे

के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य बनाता हो। शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य जब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।"

9. इसलिए, जब्ती के समय सभी पैकेटों से नमूने लेने का पीडब्लू-7 का कार्य मोहनलाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। इससे अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा होता है कि बरामद पदार्थ प्रतिबंधित था।

10. इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं है और इसे उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। तदनुसार, हम वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं और उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं।"

<u>राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँः</u>

17. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश अ.लो.अ सुश्री शशि बाला वर्मा ने तर्क दिया है कि हालांकि अभियोजन पक्ष दो स्वतंत्र गवाहों, पंकज मोहन सिंह और मोहम्मद आलम, जिनके समक्ष कथित प्रतिबंधित पदार्थों की तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया की गई थी, को पेश और पूछताछ नहीं कर सका, लेकिन अन्य सभी गवाह, जो पुलिस अधिकारी हैं, अभियोजन पक्ष की कहानी के साथ पूरी तरह से सुसंगत रहे और केवल उक्त निजी व्यक्तियों से पूछताछ न होने के कारण, अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। सुचक सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों ने गवाही दी है और स्थापित किया है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को मौके पर

ही सील कर दिया गया था और जब्ती ज्ञापन भी मौके पर तैयार किया गया था और इस साक्ष्य पर अपीलकर्ताओं द्वारा महाभियोग नहीं चलाया गया है। जहां तक नमूना लेने की प्रक्रिया का सवाल है, जांच अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं की गई है, क्योंकि उन्होंने संबंधित न्यायालय में आवेदन दिया था, जिस पर एक मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया था, जिनके समक्ष नमूने लिए गए और उसके बाद नमूने को सीलबंद हालत में विशेष दूत को सौंप दिया गया ताकि उसे एफएसएल पटना में जमा किया जा सके और रासायनिक जांच में जब्त मादक पदार्थ *चरस* पाया गया। विद्वान् अ.लो.अ ने आगे तर्क दिया है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को सीलबंद स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और अपीलकर्ता विशेष दूत सत्येंद्र तिवारी द्वारा एफएसएल पटना को तैयार किए गए नमूनों को सौंपने में कुछ देरी के कारण कोई लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं और इस संबंध में, अपीलकर्ताओं द्वारा जांच अधिकारी से जिरह नहीं की गई थी और यदि उनसे उक्त लापरवाही पर जिरह की गई होती तो देरी को समझाया जा सकता था और इसके अलावा, इस तरह की देरी केवल प्रक्रियात्मक चूक है, इसलिए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को सही ठहराया है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत, इस प्रकार, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है।

विचार और विश्लेषणः-

18. हमने दोनों पक्षों को सुना है, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों का अध्ययन किया है और आरोपी व्यक्तियों के बयानों का भी अध्ययन किया है और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

19. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों जैसे गंभीर अपराधों में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कठोरतम सबूत की आवश्यकता होती है और इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मौसम सिंह रॉय एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2003) 12 एससीसी 377** के मामले में निर्धारित सिद्धांत प्रासंगिक है।

20. मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में, मादक पदार्थ की तलाशी, जब्ती, नमूने लेने और सील करने की प्रक्रिया का बहुत महत्व है, हालांकि इनमें से किसी भी प्रक्रिया के संचालन में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक अवैधता या चूक अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं बनाएगी, जब तक कि इस तरह की प्रक्रियात्मक खामियों के कारण, यह नहीं दिखाया जाता है कि इसने आरोपी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है।

21. अब हम वर्तमान मामले पर आते हैं। तत्काल मामला अपीलार्थियों के कब्जे से *चरस* जैसे मादक पदार्थो, भरी हुई मैगजीन के साथ अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन की बरामदगी से संबंधित है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को केवल कथित मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में मुकदमे का सामना करना पड़ा और अभियोजन पक्ष के अनुसार अन्य जब्त वस्तुओं के संबंध में एक और कार्यवाही की गई, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने खुद को केवल मादक पदार्थ की बरामदगी तक ही सीमित रखा और तदनुसार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया। दोनों अपीलार्थियों ने मुख्य रूप से पाँच आधारों पर आक्षेपित फैसले पर हमला

किया है। *पहला* यह है कि दो स्वतंत्र व्यक्ति पंकज मोहन सिंह और मो. आलम, जो की अभियोजन पक्ष के अनुसार तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया को देखने वाले है, को अभियोजन पक्ष द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के पेश नहीं किया गया था और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य पर आधारित है जो अभियोजन पक्ष के मामले की सफलता में अत्यधिक रुचि रखते थे। *दूसरा* आधार यह है कि अभियोजन पक्ष नमूना लेने की प्रक्रिया को साबित करने में विफल रहा, बल्कि ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो उक्त नमूना लेने की प्रक्रिया को अत्यधिक संदिग्ध बनाती हैं और इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों का पुलिस ने सही मायने में पालन नहीं किया। *तीसरा* आधार यह है कि अभियोजन पक्ष जब्त मादक पदार्थ के साथ-साथ लिए गए नमूनों को सुरक्षित रखने में विफल रहा, जब तक कि वे एफएसएल, पटना तक नहीं पहुंच गए। *चौथा* आधार यह है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त करने के तथ्य को साबित करने में विफल रहा, जिन्हें कथित तौर पर सह-अभियुक्त समीर अंसारी द्वारा भेजा गया था, जो पुलिस दल द्वारा की गई कार्रवाई का आधार था, जबकि इस संबंध में एसपी, बेतिया से संपर्क किया गया था, जिनके निर्देश पर कई थानों के कई पुलिस अधिकारियों की एक पुलिस टीम गठित की गई थी, लेकिन इस संबंध में, ऐसी सूचना या संचार को लिखित रूप में कम करने को दर्शाने वाली कोई भी लिखित सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे प्रस्तुत किया जा सकता था यदि उसे लिखित रूप में दर्ज किया गया होता। *पाँचवाँ* आधार यह है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

22. अब, हम अपीलार्थियों द्वारा लिए गए उपरोक्त आधारों में सार का पता लगाने के साथ-साथ विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का मूल्यांकन करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों पर चर्चा करेंगे।

23. अभियोजन पक्ष के गवाह धनंजय चौधरी (अ.सा-1) ने अपनी मुख्य जांच में कहा है कि जब्ती की सूची बरामदगी के स्थान पर तैयार की गई थी। उन्होंने अपनी जिरह के पैराग्राफ नंबर 5 में कहा कि जब्त किए गए *चरस* को घटना स्थल पर सील कर दिया गया था, जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने अपनी खुद की मुहर लगा दी थी और बरामद किए गए *चरस* को बरामदगी के स्थान पर तौला गया था और थानाध्यक्ष अपने साथ तौल मशीन लाए थे। उन्होंने अपनी जिरह के पैराग्राफ नंबर 14 में आगे कहा कि जब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ खुली स्थिति में पाया गया जिसे घटना स्थल पर सील कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति पुनर्प्राप्ति स्थल के पास स्थित एक मोहल्ला के निवासी थे। अपनी जिरह के पैराग्राफ नंबर 23 में उन्होंने कहा कि जब्ती सूची के साथ आरोपी/अपीलार्थियों के संबंध में एक गिरफ्तारी ज्ञापन भी बनाया गया था।

अभियोजन पक्ष के गवाह विजय कुमार सिन्हा (अ.सा-2), जिन्हें पुलिस दल का सदस्य कहा जाता है, ने अपने जांच प्रमुख में कहा कि मादक पदार्थ सहित सभी जब्त सामग्री के संबंध में जब्ती सूची बरामदगी के स्थान पर तैयार की गई थी, जिसकी एक प्रति आरोपी को दी गई थी, जिन्हें घटना स्थल पर गिरफ्तार किया गया था। अपनी जिरह के पैराग्राफ नंबर 3 में, उन्होंने अपदस्थ किया कि जब्त किए गए *चरस* को घटना स्थल पर नहीं तौला गया था और उन्होंने अपने अनुमान के अनुसार जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के वजन का खुलासा किया।

अभियोजन पक्ष के गवाह यूसुफ अंसारी (अ.सा-3), जो पुलिस दल के सदस्य भी थे, ने अपने जाँच प्रमुख में कहा कि दो स्वतंत्र गवाहों के सामने बरामदगी के स्थान पर जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्होंने खुलासा किया कि सह-अभियुक्त समीर अंसारी द्वारा उन्हें मादक पदार्थ दिए गए थे। जब उनसे नमूने लेने के मुद्दे पर जिरह की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह तथ्य याद नहीं है कि नमूने मौके पर लिए गए थे या नहीं।

अभियोजन पक्ष के गवाह अनिल राम (अ.सा-4) ने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि जब्त किए गए *चरस* को थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने तौला था और वे एक तौल मशीन के साथ बरामदगी के स्थान पर आए थे और नमूने घटना स्थल पर लिए गए थे, जिस पर उस समय मामला संख्या नहीं लिखी गई थी। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ नंबर 6 में आगे कहा कि थानाध्यक्ष, नरेश कुमार ने घटना स्थल पर अपना आत्म-बयान तैयार किया और उसी समय आरोपी का गिरफ्तारी ज्ञापन भी तैयार किया।

24. अब हम सूचना देने वाले (अ.सा-5) के साक्ष्य पर आते हैं, जिसे संबंधित पुलिस स्टेशन के तत्कालीन थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया था और उसका साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने मुख्य जाँच अधिकारी को बताया है कि 05.10.2012 पर, वह बेतिया नगर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष के रूप में तैनात था और उस दिन लगभग 2:30 बजे सुबह को इस आशय की गुप्त सूचना मिली कि एक समीर अंसारी ने एक पुन्नू श्रीवास्तव की हत्या करने की योजना बनाई है और उक्त योजना को लागू करने के लिए उसने अपने शूटर को भेजा है और उस दिन सुबह उसका शूटर पुन्नू श्रीवास्तव पर हमला करेगा। इसके बाद, उन्होंने पुलिस अधीक्षक, बेतिया को उक्त गुप्त

जानकारी के बारे में सूचित किया, जिनके निर्देश पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एस.डी.पी.ओ.) के नेतृत्व में कई थानों के थाना प्रभारियों (एसएचओ) और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक पुलिस टीम गठित की गई। उन्होंने आगे अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उस दिन सुबह लगभग 5:30 बजे सुबह को पूर्वी तरफ से एक मोटरसाइकिल आते देखा गया, जिस पर दो लोग सवार थे। उन्होंने सवारों को अपनी मोटरसाइकिल रोकने का संकेत दिया लेकिन पुलिस दल को देखकर, उन्होंने (सवार) रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस दल ने पकड़ लिया और उसके बाद, दो स्वतंत्र व्यक्तियों, पंकज मोहन सिंह और मोहम्मद आलम की उपस्थिति में, उनके साथ-साथ उनकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर, पूर्ववर्ती अनुच्छेद संख्या 3 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए। उन्होंने अपने जाँच प्रमुख के पैराग्राफ संख्या 8, 9 और 10 में आगे कहा है कि बरामद आग्नेयास्त्रों और *चरस* के संबंध में जब्ती सूची बरामदगी के स्थान पर तैयार की गई थी, जिसकी एक प्रति अभियुक्तों को उनके हस्ताक्षर लेने के बाद दी गई थी। गवाह ने जब्ती सूची को अपने लिखित रूप में स्वीकार किया और उस पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किए, जिन्हें प्रदर्श '1' और '1/ए' के रूप में चिह्नित किया गया था। उनके अनुसार, जब्ती सूची के साथ-साथ उनका स्व-बयान बरामदगी के स्थान पर तैयार किया गया था और उसके बाद, उप-निरीक्षक प्रमोद कुमार को निषिद्ध पदार्थों की उक्त बरामदगी से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जिरह में, उन्होंने (अ.सा-5/सुचक) कहा है कि आरोपी/अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी ज्ञापन मौके पर तैयार किया गया था और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को एक तौल

मशीन की मदद से तौला गया था जो एक राहगीर से लिया गया था जो बरामदगी के स्थान के पास अपनी गाड़ी के साथ गुजर रहा था। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ संख्या 21 और 24 में आगे कहा कि बरामद *चरस* को घटना स्थल पर सील कर दिया गया था और उन्होंने उससे नमूने नहीं लिए थे और उन्होंने जब्त की गई सामग्री को एफएसएल, पटना नहीं भेजा था और इस संबंध में जांच अधिकारी विवरण दे सकते थे।

25. अभियोजन पक्ष के गवाह प्रमोद कुमार (अ.सा- 6) वर्तमान मामले का जाँच अधिकारी है। उन्होंने अपने जाँच प्रमुख के पैराग्राफ नंबर 5 में कहा कि जब्त किए गए नेपाली *चरस* को एफएसएल, पटना भेजा गया था।

अभियोजन पक्ष के गवाह जितेंद्र प्रसाद सिंह (अ.सा-7) संबंधित पुलिस स्टेशन के तत्कालीन मालखाना-प्रभारी थे और वह उस पुलिस दल के सदस्य नहीं थे जिसने आरोपी/अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और कथित प्रतिबंधित पदार्थों को बरामद किया था और उनका सबूत जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को पुलिस मालखाने में रखना और उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने की सीमा तक प्रासंगिक है। उसने अपने मुख्य जाँच अधिकारी को बताया था कि वह जब्त की गई वस्तुओं को बेतिया टाउन मालखाना से विचारण न्यायालय के सामने लाया था और विचारण न्यायालय के सामने पेश किए गए *चरस* सीलबंद हालत में थे। इस गवाह के मुख्य परीक्षण को दर्ज करते समय, विचारण न्यायालय ने पाया कि जो वस्तुएं पेश की गई थीं, उन्हें सील कर दिया गया था, जिसके बाद विचारण न्यायालय के निर्देश पर सील तोड़ दी गई और सील खोलने पर कथित *चरस* वाले दो पैकेट पाए गए, जिन्हें सामग्री प्रदर्शन 'I' और 'II' के रूप में चिह्नित किया गया था और इस गवाह के अनुसार, उक्त पैकेटों का कुल वजन लगभग 2 किलोग्राम

था। जिरह में, उसने गवाही दी है कि वह अदालत के आदेश का पालन करने के लिए बेतिया टाउन *मालखाना* से जब्त की गई सामग्री लाया था और जब्त की गई सामग्री पर तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेश कुमार के हस्ताक्षर थे जो उसके द्वारा विचारण न्यायालय में पेश किए गए थे।

26. उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियुक्त की बरामदगी और गिरफ्तारी के समय घटनास्थल पर जब्ती ज्ञापन/जब्ती सूची और अभियुक्त की गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष अभियुक्त की गिरफ्तारी ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहा और सुचक नरेश कुमार सहित इन गवाहों के अनुसार, जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेश कुमार की मुहर के साथ बरामदगी के स्थान पर सील कर दिया गया था। लेकिन नमूने के संबंध में, इन गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए क्योंकि अनिल राम (अ.सा-4) ने कहा कि नमूने बरामद होने के स्थान पर लिए गए थे, जबकि सूचना देने वाले नरेश कुमार (अ.सा-5) ने कहा कि उन्होंने जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों से नमूने नहीं लिए थे। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए (2) के प्रावधानों के अनुसार, जब्त किए गए मादक पदार्थ या मनः प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ, जिन्हें जब्त किया गया है, प्राप्त करने पर संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जब्त किए गए मादक पदार्थों की सूची तैयार करे, जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, निशान, संख्या आदि से संबंधित विवरण दिए जाएं, जो उक्त धारा के प्रावधानों द्वारा आवश्यक हैं और उसके बाद, अधिकारी को संबंधित न्यायालय के समक्ष एक

मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दायर करना होगा, ताकि इस प्रकार तैयार की गई सूची की सत्यता प्रमाणित की जा सके या ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रासंगिक सामग्रियों की तस्वीरें ली जा सकें या ऐसी तस्वीरों को सत्य प्रमाणित किया जा सके और ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी जब्त की गई दवाओं या पदार्थों से प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति दी जा सके और इस प्रकार तैयार किए गए नमूनों की सूची की सत्यता प्रमाणित की जा सके। लेकिन तत्काल मामले में, इस प्रक्रिया को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष किसी भी प्रकार का सबूत देने में विफल रहा है, हालांकि तर्क के दौरान, विद्वान अ.लो.अ. ने इस अदालत का ध्यान एक आवेदन की ओर आकर्षित किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों के अनुपालन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए और जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थों से आवश्यक नमूने लेने के लिए विचारण न्यायालय में दायर किया गया था, जिसका हमारे द्वारा अध्ययन किया गया है, लेकिन मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस आवेदन को विचारण न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी के साक्ष्य से साबित करने के लिए कोई मेहनत नहीं की। हालाँकि, इस आवेदन के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात् श्री डी. के. भास्कर को उन नमूनों को सील करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था जिन्होंने उसी आवेदन पर अपना समर्थन किया था कि जब्त की गई सामग्री को उनके सामने सील कर दिया गया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई अन्य समर्थन नहीं किया, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए में निहित प्रावधानों के अनुपालन को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, चूंकि, इसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि उनके समक्ष सीलबंद

अवस्था में जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई थीं उनकी स्थिति क्या थी, उस समय किस प्रकार की सील उपलब्ध थी, लिए गए नमूनों की संख्या, नमूनों का वजन, साथ ही जब्त प्रतिबंधित वस्तुओं से नमूने लेने के बाद उन्हें पुनः सील करने में किस प्रकार की सील का प्रयोग किया गया था, तथा लिए गए नमूनों को सील करने में किस प्रकार की सील का प्रयोग किया गया था, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने बहुत ही लापरवाही से काम किया।

27. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों के अनुसार, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को उनके द्वारा सही होने के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम मोहनलाल (**ऊपर**)** के मामले में पैराग्राफ संख्या 16 में की गई टिप्पणी, प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही है: -

> *"16. धारा 52-ए की उपधारा (3) के अनुसार मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र आवेदन स्वीकार करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही जब्ती की जाती है और प्रतिबंधित सामान पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या अधिकृत अधिकारी को भेजा जाता है, संबंधित अधिकारी कानूनन बाध्य है कि वह उपरोक्त उद्देश्यों के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करे, जिसमें उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना शामिल है, जिसके बाद नमूनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इस प्रकार निकाले गए नमूनों की सूची की सत्यता को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को उसके द्वारा सत्य प्रमाणित किया जाना चाहिए।"*

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों के अनुपालन को साबित करने में विफल रहा है। यद्यपि जाँच अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसके बाद एक मजिस्ट्रेट को भी प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के संबंध में एक सूची बनाने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है और साथ ही प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसी की तस्वीर भी ली गई है और उन्होंने जाँच अधिकारी द्वारा दायर आवेदन पर केवल इस तथ्य का समर्थन किया कि जब्त की गई सामग्री को उनके सामने सील कर दिया गया था। उक्त समर्थन एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए के अनुपालन को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के तथ्य के साथ-साथ उनके समक्ष सीलिंग प्रक्रिया को साबित करने में बहुत लापरवाही बरतता रहा क्योंकि जांच अधिकारी का प्रासंगिक आवेदन अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया था। इसके अलावा, संबंधित पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष द्वारा कथित प्रतिबंधित सामान को सील करने में शुरू में किस प्रकार की सील का इस्तेमाल किया गया था, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष कथित प्रतिबंधित सामान को दोबारा सील करने में किस प्रकार की सील का इस्तेमाल किया गया था, केस नंबर के संबंध में प्रासंगिक विवरण, सील किए गए पैकेट को खोलने पर उसमें पाए गए प्रतिबंधित सामान की मात्रा और नमूनों की मात्रा आदि, इस मामले के रिकॉर्ड में इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि निदेशक, एफएसएल, पटना के कार्यालय से जारी एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-'5') से पता चलता है कि नमूनों

वाले दो पार्सल विशेष मैसेंजर जीआर/208 सत्येंद्र तिवारी को ज्ञापन संख्या 3312 दिनांक 06.11.2012 के माध्यम से सौंपे गए थे, जिन्हें एफएसएल, पटना के कार्यालय में दिया जाना था, लेकिन यह दो महीने से अधिक समय के बाद उक्त कार्यालय में 19.01.2013 पर प्राप्त हुआ था और एफएसएल, पटना के कार्यालय में पार्सल तक पहुंचने में कथित अत्यधिक देरी के बारे में, कोई स्पष्टीकरण नहीं है और यह स्वीकार है कि तैयार किए गए नमूने दो महीने से अधिक समय तक उक्त दूत की हिरासत में रहे, जिससे नमूनों के साथ छेड़छाड़ की बड़ी संभावना पैदा होती है और स्थिति को समझाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति विशेष दूत सत्येंद्र तिवारी थे, लेकिन उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और उनकी जांच नहीं की गई। तदनुसार, हम जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थों के नमूने लेने की प्रक्रिया को, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है, अत्यधिक संदिग्ध पाते हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अनुसार, तलाशी, प्रतिबंधित सामान की जब्ती और उसे सील करने की पूरी कार्यवाही दो स्वतंत्र व्यक्तियों पंकज मोहन सिंह और मोहम्मद आलम के समक्ष की गई थी, जो पास के इलाके के निवासी थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया और न ही उनसे पूछताछ की गई और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। यद्यपि एक आपराधिक मामले में, विशेष रूप से निषिद्ध पदार्थों की बरामदगी से संबंधित अपराध में, अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों से पूछताछ न करने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है, जिन्हें तलाशी, जब्ती और नमूना लेने की प्रक्रिया का गवाह कहा जाता है, लेकिन ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों को पेश नहीं करने के लिए कुछ

स्पष्टीकरण होना चाहिए और उन्हें पेश नहीं करने में अभियोजन पक्ष की लापरवाही को ध्यान में रखा जा सकता है, विशेष रूप से जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है और तब भी जब नमूने लेने के प्रक्रिया के बारे में गंभीर संदेह पैदा करने वाली मजबूत परिस्थिति होती है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोहम्मद खालिद (उपरोक्त)** के मामले में की गई टिप्पणियां, जैसा कि इस निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 में चर्चा की गई है, प्रासंगिक है। हालांकि तत्काल मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, पुलिस दल एक गुप्त सूचना मिलने के बाद बरामदगी के स्थान पर आगे बढ़ा कि सह-आरोपी समीर अंसारी ने अपने शूटरों को एक पुन्नू श्रीवास्तव को मारने का निर्देश दिया और उक्त शूटर बरामदगी के दिन सुबह पुन्नू श्रीवास्तव को मारने जा रहे थे और जब आरोपी व्यक्ति कथित स्थान पर मोटरसाइकिल पर आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और तलाशी लेने पर कथित प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए और उनके कब्जे और मोटरसाइकिल से बरामद किया गया। हालाँकि, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई के बारे में अभियोजन पक्ष के उक्त आधार को मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष को उक्त गुप्त जानकारी को साबित करना चाहिए था क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, उक्त गुप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, संबंधित पुलिस अधिकारी और एसपी, बेतिया के बीच संचार किया गया था और उसके बाद, कई पुलिस अधिकारियों वाली एक पुलिस टीम का गठन किया गया था, इसलिए, इस संबंध में, संबंधित पुलिस थानों के संबंधित रजिस्टरों में कुछ लिखित प्रविष्टियाँ होनी चाहिए जिनमें अधिकारियों ने कथित तलाशी और जब्ती में भाग लिया था और यह

अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से साबित किया जा सकता था। इसमें कुछ सार था लेकिन इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी के बारे में संदेह पैदा होता है।

निष्कर्षः-

28. उपर्युक्त कारणों से, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों से नमूना लेने की प्रक्रिया अत्यधिक संदिग्ध है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों से नमूने लेने के समय से लेकर एफएसएल, पटना के कार्यालय तक पहुँचने तक सुरक्षित रखने को साबित करने में विफल रहा है और इसके अलावा, ऊपर चर्चा की गई उचित परिस्थितियाँ हैं जो दर्शाती हैं कि नमूने के साथ छेड़छाड़ की प्रबल संभावना है, जब यह दो महीने से अधिक समय तक विशेष संदेशवाहक की हिरासत में रहा था और हमने दो स्वतंत्र व्यक्तियों से बिना किसी स्पष्टीकरण के पूछताछ न करने को भी ध्यान में रखा है, जिनके समक्ष कथित प्रतिबंधित पदार्थों की तलाशी, ज़ब्ती और सील करने की पूरी प्रक्रिया की गई थी, जो अभियोजन पक्ष के विरुद्ध है। तदनुसार, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आरोपित अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सज़ा देने वाला निर्णय और आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त प्रक्रियात्मक चूक ने अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और विद्वान निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को उक्त अपराध के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया है, इसलिए हम वर्तमान अपील में योग्यता पाते हैं, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है और विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,

बेतिया, पश्चिम चंपारण द्वारा मुकदमा संख्या 32/2013 में पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश का आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.02.2018 को रद्द किया जाता है।

29. अपीलकर्ता संख्या 1, अर्थात् अशरफ अली अंसारी *उर्फ* अशरफ अली न्यायिक हिरासत में है, इसलिए, यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे वर्तमान मामले में तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, ।

30. अपीलकर्ता संख्या 2, अर्थात् बबलू हजाम पहले से ही जमानत पर है, इसलिए, उसके साथ-साथ उसके जमानतदारों द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसे उसके बांड से उत्पन्न होने वाली देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

31. एलसीआर को तुरंत विचारण न्यायालय में वापस भेजा जाए।

32. निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के साथ-साथ संबंधित जेल अधिकारी को भी सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्त्ति)

मैं सहमत हूँ।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति) **(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति)**

अन्नु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।